(c) what steps Government are taking to keep the tyre prices under control?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) Tyre prices have, in the last 10 years, increased at nearly 6.9 per cent per annum.

(b) No, Sir.

(c) There is no statutory control over the prices of tyres.

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

442. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रत्येक उपक्रम को हुए लाभ और घाटे का ब्यौरा क्या है ;

(ग) घाटे में चलने के कारण ऐसे कितने उपक्रमों को बन्द कर दिया गया है या निकट भविष्य में बन्द कर दिए जाने की संभावना है ;

(घ) उनकी रुग्णता के मुख्य कारण क्या हैं और उन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा क्या श्रमिकों/कर्मकारों के हितों की सुरक्षा भी की जाएगी ; और

(ङ) मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के नए उपक्रमों के स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पांच उद्यम हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। गत तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान, केवल जिस अवधि की जानकारी उपलब्ध है, उनके द्वारा अर्जित लाभ तथा उठाई गई हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	शुद्ध लाभ/हानि (-)		
	1988-89	1989-90	1990-91
1. मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपो. लि.	0	(-) 18	(-) 33
2. नेपा लि.	(-) 514	(-) 388	620
3. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	357	(-) 90	2258
4. नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.	(-) 4466	(-) 1838	(-) 1978
5. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	(-) 4756	(-) 3232	(-) 2079

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम बन्द नहीं किया गया है। कम लाभकारिता/रुग्णता के मुख्य कारण हैं—कम उत्पादकता, क्षमता का कम उपयोग, अतिरिक्त जनशक्ति, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, पुराना संयंत्र एवं मशीनरी, आदेशों की कमी आदि। उनके कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा 5.3.1992 को संसद् के दोनों सदनों में रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1990-91 के खण्ड-I में पृष्ठ संख्या 165 पर दिया गया है। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन (मध्य प्रदेश) लि., जो रुग्ण औद्योगिक

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है, के पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन हेतु उपयुक्त योजनाए बनाने के लिये उसे औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के पास भेजा जाना अपेक्षित है। पुनरुद्धार संबंधी ऐसी योजनाए बनाते समय औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्गठन मण्डल श्रमिकों/कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिये सुझाव ले सकता है। बहरहाल, ऐसे पुनर्स्थापन संबंधी पैकेजों के कारण प्रभावित होने वाले श्रमिकों/कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिये राष्ट्रीय नवीकरण कोष भी स्थापित किया गया है।

(ङ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के नये उद्यमों में पूंजीनिवेश, तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोणों के आधार पर देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रख कर किया जाता है।

Survey of Industries conducted by National Council for Applied Economic Research

443. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the Summary report on the survey of industries conducted by the NCAER (National Council for Applied Economic Research) issued in March, 1992;

(b) what is Government's reaction to the conclusions of the report that industrial growth rate will slacken to zero percent in 1992-93; and

(c) whether the expected fall in anticipated demand will further affect industrial growth?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIAN): (a) to (c) Yes, Sir. According to the Summary Report on the Expectations Survey of Industries conducted in February, 1992 by National Council of Applied Economic Research, the expected average growth rate of household demand for goods and services is zero percent in 1992-93 while the industrial demand for goods and services is expected to be 0.3 percent during the same period. However, the report does not mention the likely rate of industrial growth in 1992-93.

The Expectations Survey was conducted prior to the presentation of the Budget on February 29, 1992. Hence it does not take account of the various policy measures announced. Several policy measures announced in the Union Budget for 1992-93 are designed to enhance demand for industrial goods and to promote industrial growth. Thus, measures like partial convertibility of the rupee, reduction of duties on capital goods, and elimination of import licensing except for a small negative list, etc. would facilitate easier availability of raw materials, components etc. while measures like reduction in statutory liquidity ratio and reduction in interest rate would facilitate easier availability of funds at lower cost for industrial development.

Slump in car industry

444. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the *Indian Express* dated the 10th April, 1992 under the caption "Slump in Passenger Car Industry likely";

(b) if so, what was the production and sale thereof during the last three years (year-wise) by the major car producing companies (company-wise);

(c) what are the reasons for recessionary trends in the car industry; and

(d) in what manner Government propose to stabilise the situation in this regard during 1992-93?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) Yes. Sir.

(b) Production & sales of passenger cars by the major manufacturers during the last three years has been as under: